बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-23
09/01/2020

जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री का जागरुकता सम्मेलन, कई योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास

➢ जल और हरियाली की रक्षा कर हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रख सकेंगे :– मुख्यमंत्री

पटना, 09 जनवरी 2020 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज भागलपुर जिले के शाहकुड प्रखंड के भुलनी ग्राम पंचायत के चाड़ा बड़गांव में जल–जीवन–हरियाली यात्रा अंतर्गत जागरूकता सम्मेलन में 584 करोड़ रूपये की 50 योजनाओं का उद्घाटन एवं 136 योजनाओं का शिलान्यास रिमोट के माध्यम से किया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी ठंड के बावजूद जल–जीवन–हरियाली जागरुकता सम्मेलन में आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि जल–जीवन–हरियाली अभियान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पर्यावरण संतुलन के लिए हमलोगों ने विचार–विमर्श कर कार्य योजना बनायी और इसे मिशन मोड में पूरा करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य वक्ताओं ने अभी जल–जीवन–हरियाली अभियान के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें बतायी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प न्याय के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। हर इलाके और हर तबके का विकास किया जा रहा है। किसी की उपेक्षा नहीं की गई है। सबों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ों/अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिए कई योजनाएँ चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल, पुलिया एवं अन्य कई विकास के कार्य किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं में जागरुकता लाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। विश्व बैंक से कर्ज लेकर पहले इसे राज्य के 06 जिलों के 44 प्रखंडों में लागू किया गया और बाद में नई पद्धति के साथ पूरे राज्य में इसे जीविका के नाम से लागू किया गया। उस समय की केंद्र सरकार ने इसी पद्धति को अपनाकर आजीविका नाम से लागू किया। अभी तक 9 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उससे 01 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जोड़ा जा चुका है। 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। महिलाओं को पुलिस सेवा में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। सात निश्चय योजना के अंतर्गत सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। बच्चियों को 5वीं कक्षा के बाद भी निरंतर स्कूल जारी रखने के लिये पोशाक योजना चलायी गई और ऊपर की कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के लिये साइकिल योजना चलायी गई। लड़कियों के साइकिल से स्कूल जाने के कारण पूरे समाज का वातावरण बदला। वर्ष 2008 में साइकिल योजना के पूर्व जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1 लाख 70 हजार थी, साइकिल योजना के बाद अब

लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर हो गई है यानि 9 लाख के करीब हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में किसी अन्य राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल नहीं है। लड़कियों के जन्म लेने पर खुशी हो इसके लिए योजना चलायी जा रही है। बच्ची के जन्म लेने पर उसके माता–पिता को दो हजार रूपये, एक साल के बाद आधार से लिंक करने पर पुनः एक हजार रूपये और सम्पूर्ण टीकाकरण सम्पन्न करा लेने पर पुनः दो हजार रूपये देने की व्यवस्था की गयी है। इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को राज्य सरकार की तरफ से 10 हजार रुपए तथा स्नातक पास करने वाली विवाहित एवं अविवाहित लड़कियों को 25 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। सरकार में आने के समय राज्य का प्रजनन दर 4.3 था जो घटकर 3.2 हो गया है। यह महिलाओं में जागृति के कारण हुआ है लेकिन इसमें और कमी लाने के लिए हमलोगों ने कई काम शुरु किये हैं। सर्वे से पता चला कि पति–पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का और बिहार का प्रजनन दर 2 है। पति–पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो देश का प्रजनन दर 1.7 और बिहार का 1.6 है। हमलोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर लड़कियों को शिक्षित किया जाए तो प्रजनन दर में कमी आएगी। हमलोगों ने हर लड़की को इंटर पास कराने के लिए काम शुरु कर दिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है। 6 हजार पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है और बाकी में काम किया जा रहा है। इस साल अप्रैल माह से सभी पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरु हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, जिसका असर बिहार पर भी दिख रहा है। बिहार में मॉनसून की समयावधि में भी बदलाव आया है। पहले मॉनसून की शुरुआत 15 जून तक हो जाती थी लेकिन अब वह भी समय पर नहीं हो रहा है। जहां पहले औसत वर्षा 1200 से 1500 मि0मी0 तक होती थी, जो पिछले 13 वर्षों में घटकर 901 मि0मी0 हो गयी है। कभी असमय वर्षा, कभी अधिक वर्षापात, कभी सुखाड़ की स्थिति बनती है। पिछले वर्ष 534 में से 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इसी वर्ष जुलाई माह में काफी वर्षा हुई, फिर अगले माह सुखाड़ की स्थिति बनी और बाद में सितंबर माह में अधिक वर्षापात से बाढ़ की स्थिति बनी। उन्होंने कहा कि चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ हमलोग लोगों की राहत के लिए हरसंभव कार्य करते हैं। हमारा मानना है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल–जीवन–हरियाली के महत्व को हम सबको समझना होगा। जलवायु में हो रहे बदलाव, पर्यावरण परिवर्तन पर चर्चा के लिए 13 जुलाई 2019 को सभी दलों के विधायकों एवं विधान पार्षदों के साथ इस पर गहन मंथन कर जल–जीवन–हरियाली अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। जीवन के एक तरफ जल है तो एक तरफ हरियाली है। जल और हरियाली है तभी जीवन बचेगा। जल और हरियाली पर ही जीवन निर्भर है। जल और हरियाली की रक्षा कर हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रख सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल–जीवन–हरियाली अभियान के लिए हम यात्रा पर निकले हैं। लोगों में जागरुकता लाने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। लोगों से संवाद कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए भूजल स्तर में वृद्धि करनी होगी और हरियाली में भी बढ़ोतरी करनी होगी। इसके लिए हम सबको मिल जुलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल–जीवन–हरियाली अभियान में 11 अवयव शामिल किए गए हैं। जिसमें एक अवयव जागरुकता है यानि लोगों को जागृत करना है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को सचेत भी करना है। बाकी 10 अवयव के अंतर्गत विभिन्न कार्य योजनाएं बनाकर काम किया जाना है। इस अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक आहर, पईन, पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार,

चापाकल को भी दुरुस्त रखा जाएगा। सार्वजनिक कुओं एवं चापाकलों के पास सोख्ता का निर्माण कराया जाएगा। सभी सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिग के माध्यम से जल संचयन कर जल को भूमि के नीचे पहुंचाया जाएगा। फसल अवशेष को भी जलाने की जरुरत नहीं है। फसल अवशेष के सदुपयोग के लिए भी काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बंटवारे के बाद राज्य का हरित आवरण क्षेत्र 9 प्रतिशत रह गया था। वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरूआत की गई और 19 करोड़ पौधे लगाए गए और राज्य का हरित आवरण बढ़कर 15 प्रतिशत तक पहुंच गया। अगले तीन वर्षों में 8 करोड़ और पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुकूल फसल चक्र अपनाए जाने की जरुरत है और मुझे खुशी है कि इस पर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर बिजली पहुंचा दी गई है, किसानों को भी बिजली कनेक्शन अलग से कृषि फीडरों के माध्यम से दिया जा रहा है। किसानों को बिजली से पटवन करने में कम खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को सौर ऊर्जा जो कि अक्षय ऊर्जा है उसके लिए काम करना होगा। सभी सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की मांग पर शराबबंदी की गई। कानून के तहत कार्रवाई तो की ही जा रही है लेकिन इसके लिए जागृति भी उतना ही आवश्यक है। सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत ताड़ी कार्य से जुड़े परिवारों एवं हाशिए पर के परिवारों को वैकल्पिक रोजगार के लिए 60 हजार से एक लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है और 1 हजार की दर से 7 माह तक सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। शराबबंदी के बाद समाज में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे बौनेपन के शिकार होते हैं और महिलाएं कई बीमारियों की शिकार होती है। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी 2020 को जल–जीवन–हरियाली अभियान के पक्ष में और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ एवं शराबबंदी एवं नशामुक्ति के पक्ष में मानव श्रृंखला में आप सब शामिल होकर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएं। 16 हजार किलोमीटर तक बनने वाली इस श्रृंखला में आप सब उस दिन 11.30 बजे से 12 बजे तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी एकजुटता दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग काम में लगे रहते हैं काम का प्रचार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में चलायी जा रही कई अच्छी योजनाओं को केंद्र सरकार भी लागू करती है। हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली–नाली का निर्माण कराया जा रहा है जो इस वर्ष पूर्ण हो जाएगा। हर घर शौचालय का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अगर पीने का स्वच्छ पानी और खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए तो 90 प्रतिशत बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि 16.75 कि0मी0 लंबे भागलपुर बाइपास का निर्माण कराया गया है। तिलकामांझी विश्वविद्यालय में 100 बेड वाले छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है और कई कार्यों का उद्घाटन किया गया है। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है उसे समय पर पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि विकास के कामों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। जब से हमें काम का मौका मिला है। समाज में किसी के प्रति अन्याय नहीं होने दिया है और जो भी अन्याय करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम सबको समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। अगर समाज में सौहार्द्र का माहौल रहेगा तो विकास का लाभ सभी को सही मायने में मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग रहना होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को पौधा, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र भेंटकर एवं फूलों की बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मुख्यमंत्री ने भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के भुलनी ग्राम पंचायत के चाड़ा बड़गांव में पंचायत सरकार भवन परिसर के पास जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत जीर्णोद्धार कराए गए पोखर का सौंदर्यीकरण, पाथ–वे निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का उद्घाटन भी किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। कृषि यांत्रिकी योजना के अन्तर्गत कृषि बैंक की स्थापना हेतु लाभुकों को चेक भी दिये गये। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन परिसर में वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत सरकार भवन की बाउंड्री करायी जाय।

कार्यक्रम को भवन निर्माण मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री श्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा, सांसद श्री अजय मंडल, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती कहकशां परवीन, विधायक श्री सुबोध राय, विधायक श्री लक्ष्मीकांत मंडल, विधान पार्षद श्री संजीव सिंह, मेयर श्रीमती सीमा साह, जिला परिषद अध्यक्ष श्री अनंत कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वी0सी0 श्री अजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सह जिले के प्रभारी प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, भागलपुर प्रमंडल की आयुक्त श्रीमती वंदना किनी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन डी0, जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आशीष भारती, अन्य गणमान्य व्यक्ति, वरीय अधिकारीगण, जीविका की दीदियां एवं बड़ी संख्या में आमलोग उपस्थित थे।

******